



वो कौन सी महत्वपूर्ण ताकतें व कारक थे जिनके कारण 4000 वर्ष पहले चीन की संस्कृति में उल्लेखनीय उद्विकासी उछाल आया? एक नए शोध ने एक बड़ी सांस्कृतिक तरक्की चिन्हित की है, जिसने संस्कृति में उच्च स्तर के बदलाव की शुरुआत की। शोधकर्ताओं का दावा है कि, शराब बनाने की तकनीक में हुए एक महत्वपूर्ण आविष्कार, जिसने "मास बिअर प्रोडक्शन" को संभव बनाया, का प्राचीन चीनी लोगों पर गहरा असर पड़ा। इस आविष्कार ने, इन लोगों के लिए, विशाल स्तर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब सेवन का मौका संभव बनाया। चीन तथा युनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने, "आर्किओलॉजिकल एण्ड एन्थ्रोपोलॉजिकल साइन्सेज" नाम के जर्नल में अपना अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि, "मास बिअर प्रोडक्शन टेक्नॉलजी" के परिणामस्वरूप प्राचीन चीन के नवपाषाण युगीन लोगों में जानकारी का आदान-प्रदान तथा व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गईं। वैज्ञानिकों ने अपने लेख में लिखा है कि, इस "फरमेंटेड एल्कोहॉल प्रोडक्ट" को लेकर जो उत्साह व जोश था, उसने ही अंततः राजवंशीय चीनी सभ्यता के जन्म की शुरुआत की। कुछ विशेष सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा पैदा हुए नए सामाजिक संपर्क ऐसे बीज हैं, जिनसे अधिक बड़ी, अधिक विकसित और अधिक महत्वाकांक्षी सभ्यताएं उभरकर आ सकती हैं। तथा हजारों साल पहले चीन में, मास बिअर प्रोडक्शन ने, बड़े समारोहों और इनके परिणामस्वरूप बड़े सोशल नेटवर्क के लिए एक प्रमुख रास्ता मुहैया करवाया। चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आस-पास प्राचीन चीनी सभ्यता लोगों को नजदीक लाने वाली और आपस में जोड़ने वाली होने लगी। विभिन्न शक्तियों व कारकों के कारण पूर्व के विभाजन खत्म होने लगे। इन परिस्थितियों ने चीन के प्रथम राजवंश, शिया राजवंश के आरोहण के लिए, 2070 ईसा पूर्व के आसपास मंच तैयार किया। शिया राजकुल के नेता, एक ऐसे देश में प्रभावी रूप से शासन करने में सफल रहे जो अब एक संयुक्त उद्देश्य व पहचान को अधिक मजबूती से महसूस कर रहा था और 4000 वर्ष पहले चीन में आए इस उद्विकासी उछाल में मास बिअर प्रोडक्शन बहुत मददगार साबित हुआ। सन् 2021 में प्रकाशित, डार्टमथ कॉलेज के एक अध्ययन में सामने आया कि, चीन के जेरॉंग प्रान्त के एक कब्रगाह से खुदाई में मिले, अनुष्ठानों में काम आने वाले बर्तनों में रैंड राइस बिअर के संरक्षित अंश थे, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि, विशेष रूप से इस ट्रिंक का बहुत लंबे समय से सेवन किया जा रहा था।

बाइकों की धरपकड़

जोधपुर, 23 जून (का.सं.)। जोधपुर शहर में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस बाइकर्स पर नजर रखे हुए है। एक अभियान के तहत उन बाइकर्स की बाइक जब्त कर रही है जो एयर पॉल्यूशन बढ़ा रही है। बाइकर्स अपनी बाइक में साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं। इससे साइलेंसर से आवाज तेज हो जाती है और स्पार्किंग से पटाखे की तरह आवाज निकालते हैं।

■ एक ही दिन में आठ बाइक पकड़ीं और जूरुमां लगाया। अब तक 35 गाड़ियां जब्त की गयी हैं जोधपुर में।

ट्रैफिक पुलिस कार्यवाही कर इस तरह ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज एक दिन में रिक्रिया बैरुजी चौराह पर 8 बाइक जब्त की गईं। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने एक ही दिन में एक पॉइंट से 8 बाइक जब्त करने की सफलता पर एडीसीपी चैन सिंह माहेचा खुद मौके पर पहुंचे और टीम को बधाई दी। एडीसीपी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज

बीदासर, 23 जून (नि.सं.)। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। युवती के मामा ने मौहल्ले के दो युवकों के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार युवती के मामा ने मामला दर्ज करवाया कि 22 जून को "हम सारे परिवार सहित चूरु मायरा

■ बीदासर में एक 20 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के मामा ने मौहल्ले के दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

भरने के लिये गये थे और मेरी वृद्ध मां को भाई के घर छोड़कर गये थे। उनकी देखरेख के लिये मेरी भानजी को घर पर ही छोड़कर गये थे। गत 22 जून की रात्रि में करीब 11 बजे मौहल्ले के ही दो युवकों ने घर में प्रवेश किया ये लोग भानजी के साथ गलत हरकत करने लगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इतिहास में पहली बार मेवाड़ के पांच विधायक राष्ट्रपति पद के प्रस्तावक होंगे

राष्ट्रपति पद चुनाव में प्रस्तावक के रूप में दिल्ली पहुंचे मेवाड़ के 5 आदिवासी विधायक

उदयपुर, (का.सं.)। भाजपा नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस (एन.डी.ए.) द्वारा आदिवासी महिला द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बाद मेवाड़ के आदिवासी विधायकों को प्रस्तावक बनने के अवसर मिला है और मेवाड़ के पांच विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं।

भाजपा आलाकमान के शांति नोटिस के बाद गुरुवार को दिल्ली पहुंचने वाले ये 5 विधायक हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से विधायक फूलसिंह मीणा, सलूमर विधान सभा से अमृतलाल मीणा, झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र से बाबूलाल खराड़ी, पिण्डवाड़ा से सम्भाराम गरासिया, घड़ी

से कैलाश मीणा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाने का कार्ड खेलने के बाद भाजपा

■ जैसा कि विदित ही है, आदिवासी विधायकों के लिए राजस्थान में 25 तथा गुजरात में 27 सीटें आरक्षित हैं।

ने प्रस्तावक भी आदिवासी विधायकों को बनाया है। गौरतलब है कि राजस्थान व गुजरात में आदिवासियों की काफी संख्या है और विधानसभा में आदिवासियों के लिए राजस्थान में 25

तथा गुजरात में 27 सीटें आरक्षित हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेवाड़ अंचल मेवाड़ के पांच विधायक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रस्तावक बनेंगे। प्रस्तावकों की घोषणा होने के बाद उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि उनके परिवार में दो लोग बीमार हैं लेकिन यह काम महत्वपूर्ण होने के कारण वे दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाने दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।

विधायकों को शांति नोटिस पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंघवी, सैलजा सी.डब्ल्यू.सी. में

■ -जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) का विस्तार कर दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (63) तथा हरियाणा की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

■ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का विस्तार करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी व कुमारी सैलजा को सी.डब्ल्यू.सी. का सदस्य नियुक्त किया।

कुमारी सैलजा (59) को इसका सदस्य नामजद कर दिया। ज्ञातव्य है कि सी.डब्ल्यू.सी. कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है। उन्होंने पूर्व सांसद तथा फिल्म (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्ततोगत्वा शिव सेना की कमान ठाकरे परिवार के हाथ में ही रहेगी?

अभी तक मु.मंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे प्रकरण में न तो बागी शिव सैनिकों को ना ही भाजपा को कुछ भी भला बुरा कहा है

■ -श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जून। राजनैतिक टिप्पणीकारों के विभिन्न वर्ग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के राजनैतिक अन्त का मसिया लिखने में लगे हुये हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि ठाकरे इस समय एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। कुल 42 विद्रोही विधायक, जिनमें 7 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, असम में डेरा डाले हुये हैं तथा मुख्यमंत्री के "पहुँच से परे" होने, जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। ठाकरे बगावती विधायकों से मुम्बई लौट आने की अपील कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि अगर पार्टी विधायक कहते हैं तो वे मुख्यमंत्री पर से त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं। भाजपा इन दोनों समस्याओं का आँकलन कर रही है, उन्हें तोलकर देख रही है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे-गुट गुट के समर्थन से सरकार बनाई जाये या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लावा दिया जाये।

महाराष्ट्र के घटनाक्रम से भाजपा के खेमे में जो खुशी की लहर दौड़ रही है, उसके कारण साफ हैं। सबसे पहला कारण- महाराष्ट्र सर्वाधिक धनवान राज्य है तथा 467 अरब अमेरिकन

■ भाजपा इस पूरे प्रकरण से अभी तक काफी प्रसन्न है। पहला कारण तो यह है कि, देश का सबसे "कैश रिच" राज्य, जिसकी जी.डी.पी. 467 अरब डॉलर है, अब विपक्ष के नियंत्रण से निकल रहा है। दूसरी वजह है, "बाल ठाकरे" परिवार की छवि को धक्का लगा है, और इससे राज्य में शुद्ध भाजपा सरकार बनने की संभावना मजबूत होती है।

■ पर अभी उद्धव ठाकरे को खत्म मानना, तार्किक रूप से भी सही नहीं।

■ ठाकरे के मु.मंत्री निवास छोड़ कर ठाकरे परिवार के परम्परागत घर पर शिफ्ट होने से उन्हें जन सहानुभूति मिली है।

■ बड़ी होशियारी से उन्होंने बागी शिव सेना विधायकों के पहले तो गुजरात के सूरत शहर शिफ्ट होने, और फिर आसाम जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। महाराष्ट्र बनाम गुजरात का मुद्दा भी नहीं बनाया। और, बार-बार बागियों को महाराष्ट्र लौटने का आह्वान कर रहे हैं; इसका भी अच्छा असर हो रहा है। शिव सैनिकों पर।

डॉलर की जी.डी.पी. वाले इस राज्य की जी.डी.पी. सभी राज्यों से ज्यादा है तथा इतना समृद्ध एवं समृद्ध राज्य विपक्षियों की पकड़ से बाहर हो जायेगा। दूसरा कारण- ठाकरे की ब्रॉन्ड वैल्यू

आंशिक रूप से तो कम हो ही जायेगी तथा उनकी छवि खराब हो जाने से भविष्य में महाराष्ट्र में भाजपा के लिये, अपने बल पर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जायेगा। लेकिन संकट यह है

कि शिवसेना की राजनीति ठाकरे परिवार के साथ जुड़ी रही है तथा आगे भी इसी परिवार से जुड़ी रहेगी। अभी तक, उद्धव ठाकरे ने न तो एकनाथ शिंदे गुट की आलोचना की है और न भाजपा पर ही दोषारोपण किया है।

यद्यपि शिंदे गुट सबसे पहले भाजपा-शासित गुजरात ही गया था, फिर भी शिवसेना प्रमुख ने "गुजरात बनाम महाराष्ट्र" के परम्परागत प्रचार एवं अभियान का सहारा नहीं लिया है। अगर उद्धव ठाकरे ने इस प्रकार के मुद्दों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने का आह्वान कर दिया, तो महाराष्ट्र की नई सरकार के समक्ष कानून-व्यवस्था की समस्या से निबटने की समस्या पैदा हो सकती है। हालाँकि, इतनी बड़ी संख्या में पार्टी विधायकों के पार्टी से चले जाने पर वे भीचक्के एवं स्तब्ध हैं, फिर भी, ठाकरे अपने पते बड़ी सवाधानी एवं संतर्कता से खेल रहे हैं। उन्होंने अपना सरकारी बँला छोड़ दिया है तथा अपने पुराने एवं पौरुष मकान, "मातोश्री" में चले गये हैं। उनका यह

कदम एक ऐसा कदम है कि इससे उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन की लहर पैदा करने में मदद मिलेगी। वे विद्रोही विधायकों से बार-बार लौट आने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी के "सैल्स एजेन्ट" कौन?

कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि, प्र.मंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव लगाया कि, अडानी ग्रुप को "पवन ऊर्जा" प्लांट लगाने का काम दिया जाये

■ -जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अडानी के "सैल्स एजेंट" के रूप में कार्य कर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बनाने और सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.) द्वारा अडानी ग्रुप को ऋण देने के बार-बार किए गए रहे प्रयासों को लेकर गुरुवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) से मांग की कि वह इनकी जांच करे। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजपक्षे पर दबाव बनाया था कि वह एक विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को दे दे।

पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे यहाँ अनेक उदाहरणों में से केवल दो उदाहरण ही दे रहे हैं, जहाँ केंद्रीय एजेंसियों, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है, ने नज़रें बचा लेना बहतर

■ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मांग की कि, ई.डी. जाँच करे कि, प्र.मंत्री लगातार अडानी ग्रुप के "सैल्स एजेन्ट" के रूप में काम क्यों कर रहे हैं।

समझा। उन्होंने कहा कि पहले प्रकरण में, श्रीलंका के सरकारी स्वामित्व वाले "सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" के चेयरमैन ने उस देश के संसदीय पैरल के समक्ष मोदी की यह भूमिका उजागर की थी। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि "माननीय प्रधानमंत्री (मोदी) एक दूसरे देश (श्रीलंका) में (भारत के) एक व्यक्ति विशेष को व्यवसायिक लाभ देने के लिये कथित रूप में जोर दे रहे थे। वल्लभ ने पूछा कि क्या प्रष्टाचार का यह

केस जाँच-पड़ताल किये जाने योग्य नहीं है।

एक अन्य प्रकरण के अनुसार, मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आते ही एस.बी.आई. ने अडानी ग्रुप के साथ 1 अरब डॉलर (7,825 करोड़ ₹) का सैद्धान्तिक इकरारनामा (इन-प्रिन्सिपल एग्रीमेंट) तैयार किया था, लेकिन इसे वापस लेना पड़ा तथा एम.ओ.यू.रद्द कर देना पड़ा। 2020 में, एस.बी.आई. ने अडानी के ऑस्ट्रेलिया स्थित का निकेल कोयल प्रोजेक्ट का 5000 करोड़ ₹ का एक अन्य ऋण दे दिया। यह निवेशकों के दबाव के कारण रूका पड़ा है। पिछले एक साल ऋण की रिश्ति (लोन स्ट्रेट्स) के बारे में अद्यतन जानकारी नहीं मिली है।

प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि यह सब ऐसा लगता है, जैसे किसी ने अडानी ग्रुप को ऋण उपलब्ध कराने के लिये संयुक्त प्रयास किया गया था। क्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दवा मर्ज से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है!

मंहगाई (इन्फ्लेशन) पर काबू पाने के लिये, बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। आशा है जनता कम पैसा उधार लेगी बैंकों से, तो मार्केट में "करैन्सी" कम होगी, अतः, चीज़ों के दाम कम होंगे

■ -अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। क्या दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है? इस तथ्य को लेकर जितनी गंभीरता बरती जा रही है, यह प्रश्न उतनी ही तेजी से उभर रहा है। दुनिया के केन्द्रीय बैंक मंहगाई पर लगातार कसने को लेकर जो नीतियां बना रहे हैं, उनसे मंदी आ सकती है तथा और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ सकती है।

हमने अब तक रुस की वर्ष 1917 की क्रांति के बारे में जाना है कि "वे दस दिन ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वर्तमान में अब ऐसा ही एक दृष्टिकोण जनमानस में अपनी जगह बना रहा है।"

लंदन की इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन दुनिया के बड़े केन्द्रीय बैंकों द्वारा नए सिरे से बनाई गई नीतियों का उल्लेख उन आठ दिनों के रूप में कर रही है, जिन्होंने

दुनिया को हिला दिया। मैगज़ीन कहती है कि इनकी शुरुआत सैन्ट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से हुई। उसके बाद यूरोपियन सैन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान और फिर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि की।

हमारे खुद के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) ने इनका पूर्वानुमान प्रवृत्त हो कर लिया था और ब्याज दरें पहले ही बढ़ा दी थी। रिजर्व बैंक कह रहा है कि जब तक मंहगाई नियंत्रित नहीं हो जाती, कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। वास्तव में आर.बी.आई. यह चेतावनी दे रहा है कि दो वर्षों तक रही कोविड की वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को देखते हुए यह भी जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाले कारक मंद ना पड़ जाएं।

■ पर, अगर, "औद्योगिक एक्सपैन्शन" कम हुआ, क्योंकि लोग उत्पादन बढ़ाने के लिये मशीनों, रॉ मटीरियल कम खरीदेंगे, तो, बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ने से, मार्केट में बिक्री कम होगी और दाम बढ़ेंगे।

■ ब्याज दर बढ़ाने का यह नतीजा होगा, यह आशंका तो थी ही। पर, अब यह आशंका यथार्थ में बदलती जा रही है, विश्व में। उदाहरण के लिये, अमेरिका में मंहगाई उस स्तर पर पहुंच गयी है, जहां गत चालीस साल में नहीं पहुंची थी।

■ भारत की स्थिति जरूर कुछ फर्क है। भारत की इकॉनमी "इनवर्टेड लुकिंग" है, अतः ब्याज दर बढ़ने के बावजूद, औद्योगिक उत्पादन घटा नहीं है।

बहरहाल, थोड़ा बहुत भय है। ब्याज दरों में वृद्धि वित्तीय बाजारों में एक ऐसी स्थिति निर्मित कर रही है जो विकास के लिए अभिशाप है। वैश्विक

वित्तीय बाजारों में पहले ही घबराहट है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से वे बच नहीं पा रहे हैं। ब्याज दरों में हुई वृद्धि के दो पहलू

हैं। पहला तो ब्याज दरों में वृद्धि मुख्यतः मंहगाई का मुकाबला करने के लिए की गई है। पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ देशों में तो कीमत वृद्धि अभूतपूर्व रही है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मंहगाई की दर 8.6 प्रतिशत रही जिसे पिछले 40 वर्षों में सर्वाधिक बताया जा रहा है। कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि जनता क्रुद्ध हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने देश की जनता को सार्वजनिक रूप से पुनःआश्वासन करना चाहते हैं कि वह बढ़ती कीमतों से हो रही मुश्किलों को कम करने के लिए हरसंभव प्रयत्न करेंगे। आगामी मध्यवर्ती चुनावों के संदर्भ में इसकी आवश्यकता ज्यादा ही बढ़ जाती है।

दूसरा ब्याज दरों में वृद्धि की चर्चा पिछले कुछ समय से एक सुधारवादी उपाय के रूप में की जा रही है जो कि

ऐसी विशिष्ट मौद्रिक नीतियां हैं जिन्हें वैश्विक महामारी के विपरीत प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अपनाया गया है। वैश्विक महामारी के कारण उभरते बाजारों और गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी कमी आ गयी। लॉकडाउन और नौकरियां खोने के कारण जनता को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सब्सिडीज, राशन तथा नकद राशि दी गयी। अधिकांश देशों में वित्तीय घाटा बढ़ चुका है। वास्तव में, वर्ष 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद से ही समायोजक कदम उठाए जाने शुरू हो गये थे और कुछ हल्के रूप में ये आज भी जारी है। इन्हें कभी ना कभी पलटा जाना होगा और आर्थिक नीति के मार्पदंडों को सामान्य स्तरों पर लाना होगा।

तथापि, जब कभी भी ब्याज दरों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेप के आरोपी को सजा

अलवर, (नि.सं.)। अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर एक में जज ने रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़िता ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया था, लेकिन सवातों के आधार पर जज ने आरोपी को सजा

■ हालांकि पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी को पहचानने से मना कर दिया पर कोर्ट ने डी.एन.ए. और एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर रेप होना माना व आरोपी को दस साल की सजा सुनाई।

सुनाई। नाबालिग के पिता ने ही आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन बाद में कोर्ट में मुकर गया और नाबालिग ने भी आरोपी को पहचानने से मना कर दिया। इस पर कोर्ट ने एफएएसएल और डीएनए रिपोर्ट के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)